Current Affairs | With Reference to the Official Website of Reserve Bank of India (RBI) | MAY 2021

Highlights of Governor's Statement - May 5, 2021 | Important Data & Key Takeaways

⇒ आरबीआई कोविड महामारी के खिलाफ एक कैलिब्रेटेड और व्यापक रणनीति के पहले भाग के रूप में काम करने का प्रस्ताव रख रहा है।

⇒ अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने वैश्विक विकास के अनुमान को 6 प्रतिशत कर दिया।

⇒ World merchandise trade ने अपने वर्तमान अपट्रेंड को बनाए रखते हुए 2021 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की है।

⇒ विशेष रूप से संपर्क-गहन सेवाओं में, कुल मांग की स्थिति एक अस्थायी गिरावट देखने की संभावना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि COVID स्थिति कैसी है।

⇒ विनिर्माण के लिए Purchasing managers' index (PMI) अप्रैल 2021 में 55.5 पर विस्तार क्रम में जारी रहा, जबकि पिछले महीने में यह 55.4 था।

⇒ मार्च 2021 में CPI मुद्रास्फीति बढ़कर 5.5% हो गई, जो कि एक महीने पहले 5.0% थी।

⇒ बाहरी क्षेत्रों में, मार्च 2021 में भारत में निर्यात और आयात तेजी से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समग्र रूप से, व्यापारिक व्यापार घाटा 2019- 20 के 161 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 98.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

⇒ विदेशी मुद्रा भंडार में 30 अप्रैल को 588 अरब अमेरिकी डॉलर था।

⇒ अप्रैल 2021 में चलनिथि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत औसत दैनिक शुद्ध चलनिधि अवशोषण ₹5.8 लाख करोड़ था।

Additional Measures announced by the RBI Governor

⇒ लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (SLTRO)

⇒ लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा एमएफआई को उधार देना प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए

⇒ MSME उद्यमियों को ऋण

⇒ आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुँचने के लिए ₹50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी सुविधा।

Resolution Framework 2.0 for COVID Related Stressed Assets of Individuals, Small Businesses and MSMEs.

⇒ उधारकर्ता यानी जिन व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय तथा MSME का कुल एक्सपोजर ₹25 करोड़ तक है और जिन्होंने पहले के किसी भी पुनर्गठन ढांचे के तहत पुनर्गठन का लाभ नहीं उठाया है (6 अगस्त, 2020 के Resolution Framework 1.0 के तहत), और जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ' 31 मार्च, 2021 को Resolution Framework 2.0 के तहत विचार किए जाने के पात्र होंगे।

⇒ व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के संबंध में, जिन्होंने Resolution Framework 1.0 के तहत अपने उधारों के पुनर्गठन का लाभ उठाया है, जहाँ संकल्प योजना ने दो साल से कम की मोहलत की अनुमति दी है, उधार देने वाली संस्थाओं को इस तरह की योजनाओं को संशोधित करने के लिए moratorium की अवधि और/या शेष अवधि को कुल 2 वर्ष तक बढ़ाकर इस विंडो का उपयोग करने की अनुमति है।

Rationalisation of Compliance to KYC Requirements

⇒ ग्राहकों की नई श्रेणियों के लिए V-CIP (video-based customer identification process- वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) के रूप में ज्ञात वीडियो KYC के दायरे का विस्तार करना।

⇒ आधार e-KYC प्रमाणीकरण के आधार पर खोले गए सीमित KYC खातों को non-face-to-face मोड में पूरी तरह KYC-अनुपालन खातों में परिवर्तित करना।

⇒ V-CIP के लिए केंद्रीकृत KYC रजिस्ट्री (CKYCR-Centralised KYC Registry) के KYC पहचानकर्ता के

उपयोग को सक्षम करना और पहचान प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जमा करना।

⇒ ग्राहकों के KYC विवरण को समय-समय पर अपडेट करने के उद्देश्य से डिजिटल चैनलों के उपयोग सहित अधिक ग्राहक-अनुकूल विकल्पों का परिचय।

Utilisation of Floating Provisions and Countercyclical Provisioning Buffer

⇒ बैंकों पर महामारी से संबंधित तनाव को कम करने के लिए और पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, बैंकों को 31 दिसंबर, 2020 तक उनके द्वारा धारित floating provisions/countercyclical provisioning buffer का 100% उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। इस तरह के उपयोग की तत्काल प्रभाव से लेकर 31 मार्च, 2022 तक की अनुमति है।

Relaxation in Overdraft (OD) facility for States Governments

⇒ राज्य सरकार के लिए आयुध डिपो के दिनों की अधिकतम संख्या एक तिमाही में 36 से 50 दिन और इसके लगातार दिनों की संख्या 14 से 21 दिन तक बढ़ाई जा रही है। यह सुविधा 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी।

All Current Affairs from RBI Website | May 2021

Directions under Section 35A, Section 56, Banking Regulation Act, 1949 | Rupee Co-operative Bank Ltd

⇒ भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 फरवरी, 2013 पर कारोबार की समाप्ति के बाद रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को अपने दिशा-निर्देश में रखा है। इसकी वैलिडिटी बार-बार बढ़ाई जा रही थी जो कि आखिरी बार 31 मई, 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है।

RBI Governor meets MD & CEOs of Public Sector Banks over Video Conference

⇒ आरबीआई के गवर्नर ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की।

⇒ बैठक में आरबीआई के उप राज्यपाल श्री एम. के. जैन, श्री एम. राजेश्वर राव, डॉ. माइकल डी. पात्रा और श्री टी. रबी शंकर ने भी भाग लिया।

⇒ उन्होंने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के दौरान व्यक्तियों और व्यवसायों को ऋण सुविधाओं सहित विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

⇒ मीटिंग में निम्नलिखित मुद्दों पर बात की गई-

- ✓ Current state of the financial sector; वित्तीय क्षेत्र की मौजूदा हालत
- ✓ छोटे उधारकर्ताओं, MSME आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रवाह।
- ✓ कोविड समाधान फ्रेमवर्क 1.0 के कार्यान्वयन में प्रगति;
- ✓ मौद्रिक नीति संचरण; तथा
- ✓ आरबीआई द्वारा किए गए कोविड से संबंधित नीतिगत उपायों का कार्यान्वयन।

Update on PSL (Priority Sector Lending) Norms

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL- Priority Sector Lending) दिशानिर्देश जारी किए। हाल ही में PSL दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने

में मदद करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उधार नीतियों को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना है।
इस समीक्षा में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू.के. सिन्हा) और 'कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह समिति (अध्यक्ष: श्री एमके जैन) के साथ ही सभी हितधारकों द्वारा की गई सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया।

Threshold Level of Inflation – Concept and Measurement

आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर डीआरजी स्टडी* शीर्षक "मुद्रास्फीति का दहलीज स्तर - अवधारणा और माप" जारी किया।
अध्ययन के सह-लेखक प्रोफेसर रवींद्र एच. ढोलकिया, डॉ. जय चंदर, श्रीमती हैं। इप्सिता पाधी और श्री भानु प्रताप।
अध्ययन थ्रेशोल्ड मुद्रास्फीति की अवधारणा की जांच करता है और इसे मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक संतुलन दर के रूप में परिभाषित करता है जो मूल्यों की प्रासंगिक सीमा के भीतर स्थिर राज्य वृद्धि को अधिकतम करता है।

Risk Premium Shocks and Business Cycle Outcomes in India

⇒ आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर DRG स्टडी शीर्षक " Threshold Level of Inflation – Concept and Measurement" जारी किया।
⇒ इस अध्ययन को सह-लेखन करके प्रोफेसर रवींद्र एच. ढोलकिया, डॉ. जय चंदर, श्रीमती इप्सिता पाधी और श्री भानु प्रताप ने लिखा है।
⇒ यह अध्ययन थ्रेशोल्ड मुद्रास्फीति की अवधारणा की जांच करता है और इसे मूल्यों की प्रासंगिक सीमा के भीतर स्थिर राज्य वृद्धि को अधिकतम करते हुए मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक संतुलन दर के रूप में परिभाषित करता है।

589th Meeting of Central Board of the Reserve Bank of India

⇒ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई।
⇒ बोर्ड की बैठक के द्वारा अर्थव्यवस्था पर COVID-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के लिए नीतिगत उपायों की समीक्षा की गई।
⇒ रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष जुलाई-जून से बदलकर अप्रैल-मार्च कर दिया।
⇒ आरबीआई ने 31 मार्च, 2021 (जुलाई 2020-मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष (surplus) के रूप में ₹ 99,122 करोड़ के हस्तांतरण को मंजूरी दी।

Important Points on Prepaid Payment Instruments (PPIs)

⇒ PPI interoperability को अनिवार्य बनाया गया।
⇒ पूर्ण-KYC PPIs को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख किया गया।
⇒ गैर-बैंक PPI जारीकर्ताओं के पूर्ण-KYC PPI का उपयोग करके नकद निकासी की अनुमति दी। इसकी शर्तें ये हैं-
⇒ हर PPI पर 10000 रु. प्रतिमाह की कुल सीमा के साथ 2000 रु. प्रति लेनदेन की अधिकतम सीमा।

RBI appoints Shri Jose J. Kattoor as new Executive Director

⇒ श्री जो सजे. कट्टूर को कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया गया।
⇒ कार्यकारी निदेशक के रूप में वह मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति तथा बजट और राजभाषा विभाग देखेंगे।

RBI cancels the licence of United Co-operative Bank Ltd., Bagnan, West Bengal

⇒ आरबीआई ने United Co-operative Bank Ltd., बगनान, प. बंगाल का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
⇒ इसे बैंकिंग व्यवसाय को करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

RBI cancels the licence

⇒ आरबीआई ने शिवाजाराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र का लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने पर रद्द कर दिया।

RBI Governor meets MD & CEOs of Non-Banking Financial Company- Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs)

⇒ आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास नें एमडी/सीईओ के साथ बैठक की।

⇒ गवर्नर ने जमीनी स्तर पर ऋण को सुलभ बनाने में NBFC-MFIs की महत्ता को माना।

⇒ उन्होंने अपने व्यवसाय के लचीलेपन को बनाए रखने और विवेकपूर्ण ढंग से जोखिमों के प्रबंधन के संदर्भ में supervisory expectations पर जोर दिया।

⇒ उन्होंने NBFC-MFIs को सलाह दी की वे उचित व्यवहार संहिता के सख्त पालन पर ध्यान दें, ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करें तथा संस्थानों और उनके ग्राहकों के हित में अपने IT को मजबूत करें।

Shri T. Rabi Sankar appointed as RBI Deputy Governor

⇒ श्री टी. रबी शंकर को आरबीआई में 3 सालों के लिए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।

⇒ वे पदोन्नति से पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे।

Group of Advisors to Regulations Review Authority invites feedback and suggestions

⇒ आरबीआई ने विनियम समीक्षा प्राधिकरण (RRA 2.0), की स्थापना एक वर्ष के लिए की जिसकी शुरुआत 1 मई, 2021 से हुई।

⇒ यह आंतरिक रूप से और साथ ही आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओँ और अन्य हितधारकों से उनके सरलीकरण तथा कार्यान्वयन में आसानी पर सुझाव मांगकर नियामक नुस्खे की समीक्षा करेगा।

⇒ श्री एस. जानकीरमन, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं, इसके अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं।

Special Long-Term Repo Operations (SLTRO) for Small Finance Banks (SFBs)

⇒ व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को ऋण की आपूर्ति करने में लघु वित्त बैंक एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।

⇒ महामारी की मौजूदा लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित छोटी व्यावसायिक इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, ₹10,000 के विशेष तीन-वर्षीय दीर्घकालिक रेपो संचालन (SLTRO) का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। SFBs के लिए रेपो दर पर करोड़, प्रति उधारकर्ता ₹ 10 लाख तक के नए ऋण के लिए तैनात किया जाएगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी।

⇒ कोविड महामारी की मौजूदा लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित छोटी व्यावसायिक इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, 10000 करोड़ रुपये का विशेष तीन-वर्षीय दीर्घकालिक रेपो संचालन (SLTRO) करने का निर्णय लिया गया है। SLTRO प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के नए ऋण के लिए तैनात किया जाएगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी।

⇒ Accordingly, the Reserve Bank will conduct one auction for SLTRO each month. The first auction will be conducted on May 17, 2021 for ₹10,000 crore. आरबीआई प्रत्येक माह SLTRO के लिए एक नीलामी आयोजित करेगा। पहली नीलामी 17 मई, 2021 को 10000 करोड़ रुपये में आयोजित करेगी।

⇒ चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पात्र सभी लघु वित्त बैंक योजना में भाग ले सकते हैं।

⇒ SLTRO का आयोजन CBS (E-KUBER) प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।

⇒ न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपये होगी।

⇒ आवंटन 1 करोड़ के गुणक में होगा।

On-Tap Term Liquidity Facility to Ease Access to Emergency Health Services

⇒ देश में COVID से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल तरलता के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च, 2022 तक रेपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की on-tap liquidity window खोलने का निर्णय लिया गया है।

⇒ बैंक इस योजना के तहत, वैक्सीन निर्माताओं सहित कई तरह की संस्थाओं जैसे- वैक्सीन और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों के आयातक/ आपूर्ति कर्ता; अस्पताल/ औषधालय; पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर; ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के निर्माता और आपूर्ति कर्ता; टीकों और COVID से संबंधित दवाओं के आयातक; COVID से संबंधित logistics firms और इलाज के लिए मरीजों को नई उधार सहायता प्रदान कर सकते हैं।

⇒ बैंकों को इस योजना के तहत ऋण के त्वरित वितरण के लिए 31 मार्च, 2022 तक प्राथमिकता क्षेत्र उधार (PSL) वर्गीकरण के विस्तार के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन ऋणों को पुनर्भुगतान/ परिपक्वता तक, जो भी पहले हो, PSL के तहत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। बैंक इन ऋणों को उधारकर्ताओं को सीधे या आरबीआई द्वारा विनियमित मध्यस्थ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वितरित कर सकते हैं।

⇒ इस योजना के तहत, बैंकों से एक COVID loan book बनाने को कहा गया है। एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के माध्यम से, ऐसे बैंक रिवर्स रेपो विंडो के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपनी अधिशेष (surplus) तरलता को COVID loan book के आकार तक रखने के लिए पात्र होंगे, जो कि रेपो दर से 25 bps कम है।

⇒ चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पात्र सभी बैंक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Credit to MSME Entrepreneurs

⇒ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) की गणना के लिए नए MSME उधारकर्ताओं को उनकी शुद्ध मांग और समय देयताओं (NDTL- Net Demand and Time Liabilities) से वितरित ऋण के बराबर राशि की कटौती करने की अनुमति दी गई थी।

⇒ यह छूट 1 अक्टूबर, 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित किए गए ऋण के लिए प्रति उधारकर्ता 25 लाख रुपए तक उपलब्ध थी।

⇒ 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित ऐसे ऋण के लिए इस छूट को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

Periodic Updation of KYC – Restrictions on Account Operations for Non-compliance

⇒ देश के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान COVID-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां KYC का periodic updation देय है और आज तक लंबित है, ऐसे खाते के संचालन पर, जब तक कि किसी नियामक/प्रवर्तन एजेंसी/कानून की अदालत आदि के निर्देशों के तहत आवश्यक न हो, 31 दिसंबर, 2021 तक कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

Utilisation of Floating Provisions/Counter Cyclical Provisioning Buffer

⇒ बैंकों पर COVID 19 संबंधित तनाव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 31 दिसंबर, 2020 तक उनके द्वारा धारित floating provisions/ countercyclical provisioning buffer के 100% का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

⇒ इस तरह के उपयोग की तत्काल प्रभाव से तथा 31 मार्च, 2022 तक की अनुमति दी गई है।

Relaxation in OD facility for States Governments/UTs

⇒ आरबीआई ने राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नकती प्रवाह और बाजार उधार के मामले में अपनी वित्तीय स्थिति का बेहतर प्रबंधन करने के लिए दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा के लाभ को नियंत्रित करने वाली शर्तों में ढील दी है।

⇒ एक तिमाही में अधिकतम दिनों की संख्या, जिनपर राज्य सरकारें तथा केंद्र शासित प्रदेश ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकतें हैं, को 36 दिनों से बढ़ाकर 50 दिन कर दिया है।

⇒ इसके अलावा, लगातार दिनों की संख्या जिस पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें 14 दिनों से बढ़ाकर 21 दिन किया जा रहा है। यह सुविधा 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी।

Priority Sector Lending (PSL) - On-lending by Small Finance Banks (SFBs) to NBFC-MFIs

⇒ COVID-19 महामारी द्वारा लाई गई नई चुनौतियों को देखते हुए और छोटे MFI की आकस्मिक तरलता की स्थिति को दूर करने के लिए, SFB द्वारा पंजीकृत NBFC-MFI और अन्य MFI (Societies, Trusts etc.), जो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र के 'स्व-नियामक संगठन' के सदस्य हैं और जिनके पास व्यक्तियों को ऋण देने के उद्देश्य से 31 मार्च 2021 तक ₹500 करोड़ तक का 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' है, को दिए गए नए क्रेडिट के लिए PSL वर्गीकरण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

⇒ बैंक ऋण की अनुमति 31 मार्च, 2021 को बैंक के कुल प्राथमिकला प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक होगी।

⇒ यह छूट 31 मार्च, 2022 तक वैध होगी। हालांकि, इस प्रकार वितरित ऋणों के पुनः भुगतान तथा परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।

Sectoral Deployment of Bank Credit – March 2021

⇒ मार्च 2021 के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तैनात कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 90% के लिए चुनिंदा 33 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से एकत्र किए गए बैंक ऋण की क्षेत्रीय तैनाती पर डेटा जारी किया गया है।

Portfolio of Deputy Governor | May 2021	
Name	**Departments**
श्री एम. के. जैन	1. समन्वय, 2. केंद्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ, 3. उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग, 4. पर्यवेक्षण विभाग, 5. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, 6. मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, 7. परिसर विभाग, 8. राजभाषा विभाग , 9. सचिव का विभाग
डॉ. एम. डी. पात्रा	1. कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग 2. आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग 3. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग 4. जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम 5. वित्तीय बाजार संचालन विभाग 6. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग 7. वित्तीय स्थिरता इकाई, 8. अंतर्राष्ट्रीय विभाग, 9. मौद्रिक नीति विभाग

श्री एम. राजेश्वर राव	1. विनियमन विभाग, 2. संचार विभाग 3. प्रवर्तन विभाग, 4. निरीक्षण विभाग 5. कानूनी विभाग, 6. जोखिम निगरानी विभाग
श्री टी. रबी शंकर	1. मुद्रा प्रबंधन विभाग, 2. बाहरी निवेश और संचालन विभाग, 3. सरकार और बैंक खाते विभाग, 4. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 5. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग 6. विदेशी मुद्रा विभाग, 7. आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग 8. सूचना का अधिकार (RIA) प्रभाग

Monetary Penalty imposed by RBI- MAY 2021

S.no	Name of the Bank	Penalty Imposed	Reason
1.	**सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र**	**₹3.50 लाख**	एक्सपोजर मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध और आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (IRAC) मानदंडों पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी निर्देशों के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए
2.	**शंकर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नांदेड़, महाराष्ट्र**	**₹1.00 लाख**	एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी निर्देशों के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए - UCBs
3.	**HDFC बैंक लिमिटेड**	**₹10.00 करोड़**	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए।

Foreign Exchange Reserves as on 21st May 2021

Name of the Item	In Crores	In Millions
Total Reserves	**4318817**	**592894**
1.1 Foreign Currency Assets	**3995492**	**548519**
1.2 Gold	**275640**	**37841**
1.3 SDRs	**11020**	**1513**
1.4 Reserve Position in the IMF	**36665**	**5021**

Policy Rates in May 2021

Policy Repo Rate	**4.00%**
Reverse Repo Rate	**3.35%**

Marginal Standing Facility Rate	**4.25%**
Bank Rate	**4.25%**
CRR	**4.00%**
SLR	**18.00%**

Central Board of Directors of the Reserve Bank of India as on 1st June 2021	
श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर	मिस रेवती अय्यर (निदेशक)
श्री महेश कुमार जैन, डिप्टी गवर्नर	प्रो. सचिन चतुर्वेदी (निदेशक)
डॉ. एम. डी. पात्रा, डिप्टी गवर्नर	श्री नटराजन चंद्रशेखरन (निदेशक)
श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर	श्री सतीश काशीनाथ मराठे (निदेशक)
श्री टी. रबी शंकर, डिप्टी गवर्नर	श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति (निदेशक)
	श्री देबाशीष पांडा (निदेशक)
	श्री अजय सेठ (निदेशक)